



ONGC News, 30.11.2020 Print

बीपीसीएल को विनिवेशित पीएसयू के दर्जे के आसार

शाइन जैकब
नई दिल्ली, 29 नवंबर

केंद्र सरकार जल्द ही मंत्रिमंडल के सामने यह सुनिश्चित करने के लिए प्रस्ताव रखने वाली है कि भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन (बीपीसीएल) के रसोई गैस ग्राहकों को कंपनी के निजीकरण के बाद भी सब्सिडी मिलती रहे।

इस घटनाक्रम के बारे में जानकारी रखने वाले कई लोगों के अनुसार सरकार सब्सिडी प्रदान करने के लिए बीपीसीएल को जल्द ही विनिवेशित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) का दर्जा प्रदान कर सकती है। इस प्रस्ताव को मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने की संभावना है। हालांकि बीपीसीएल के मौजूदा एलपीजी उपभोक्ता आधार को

धीरे-धीरे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (इंडियन ऑयल) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन (एचपीसीएल) में स्थानांतरित करने की भी योजना है, जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सरकार के नियंत्रण में ही रहेंगे। हालांकि एलपीजी उपभोक्ता आधार प्रारंभिक सूचना ज्ञापन (पीआईएम) मूलाधार का ही हिस्सा था जिसके लिए सरकार ने हिस्सेदारी बिक्री के लिए रुचि पत्र मांगा था।

पेट्रोलियम नियोजन एवं विश्लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी) के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार बीपीसीएल के पास एलपीजी के लगभग 7.3 करोड़ उपभोक्ता हैं, जबकि इंडियन ऑयल के पास 13.4 करोड़ उपभोक्ता और एचपीसीएल के पास तकरीबन 7.8 करोड़ उपभोक्ता हैं।

नाम उजागर न करने की शर्त पर उद्योग के एक भागीदार ने कहा कि विनिवेशित पीएसयू का दर्जा सब्सिडी व्यवस्था जारी रखने के लिए सही रहेगा। हालांकि उपभोक्ताओं के स्थानांतरण की संभव नहीं है, क्योंकि ज्यादातर निवेशकों की निगाहें बीपीसीएल के विपणन खंड पर हैं। वेदांता लिमिटेड और अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट कथित रूप से बीपीसीएल में सरकारी हिस्सेदारी खरीदने की दौड़ में हैं। हालांकि वेदांता ही एकमात्र ऐसी कंपनी है जिसने आधिकारिक तौर पर कहा है कि उसने रुचि पत्र जमा किया है।

बीपीसीएल को विनिवेशित पीएसयू का दर्जा देने का मतलब यह हो सकता है कि सब्सिडी लाभ के लिए अन्य निजी कंपनियों पर बिल्कुल भी विचार न किया जाए।

रिलायंस इंडस्ट्रीज (आरआईएल) और नायरा एनर्जी जैसी समानांतर विपणनकर्ताओं का एलपीजी कारोबार पहले से ही सरकार द्वारा संचालित आक्रामक बड़ी कंपनियों के बीच पर्याप्त बाजार हिस्सेदारी पाने के लिए जूझना पड़ रहा था। आरआईएल, नायरा एनर्जी और टोटाल सहित निजी कंपनियों ने पहले ही सरकार से कहा था कि उन्हें सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर बेचने की अनुमति प्रदान की जाए और उन्हें सब्सिडी-अंतरण करने वाली व्यवस्था का हिस्सा बनाया जाए। देश में कुल 28.5 करोड़ तरलीकृत पेट्रोलियम गैस उपभोक्ताओं में से 26 प्रतिशत हिस्सेदारी बीपीसीएल के पास है। देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार में संबंधित उत्पादों की कीमत से जुड़ी हुई हैं।

News Wrap

Eight core sectors contract 2.5 per cent in October

India's eight key infrastructure sectors contracted for the eighth consecutive month in October, posting a decline of 2.5 per cent (year-on-year), weighed down by a fall in production of crude oil, natural gas, petroleum refinery production, and steel.

The remaining sectors posted an increase in production in October, with coal at 11.6 per cent, fertiliser at 6.3 per cent, cement at 2.8 per cent, and electricity at 10.5

per cent, as per figures released by the Department for Promotion of Investment and Internal Trade (DPIIT).

In September, the core sector contraction had narrowed to below 1 per cent, raising hopes of a resurgence in manufacturing activity and economic revival. "There were expectations that the core sector growth rate may turn marginally positive in October. However, there is some promise in the profile," pointed out Madan Sabnavis, chief economist, CARE Ratings.

Coal and power have double-digit growth rates reflecting higher economic activity in the month, relative to the earlier ones, Sabnavis said.

"Cement growth has turned positive at 2.8 per cent, which is encouraging as it reflects work in the real estate and roads sectors. However, it may be mentioned that the government expenditure on roads in the first seven months has been lower than last year," he added.

Growth in fertilisers also continues to be positive at 6.3 per cent, which is in step with rabi sowing. But it may get diluted going ahead, once the sowing is over and the companies stock their inventories.

Negative growth in steel (2.7 per cent) after positive growth last month reflects volatility in production linked with auto and infra sectors

The oil sector continued with negative growth rates as demand remained weak—both domestic and external. Refinery products, with the highest weight (28.04 per cent) in the index, registered the sharpest drop of 17 per cent during the month. It was followed by fall in natural gas production at 8.6 per cent and crude oil at 6.2 per cent. IIP growth would probably still be negative this month in the region of 0 per cent -1 per cent, Sabnavis said.



Gas distribution shares soar as competition overhang lifts

Ujval Jauhari
 ujval.j@livemint.com

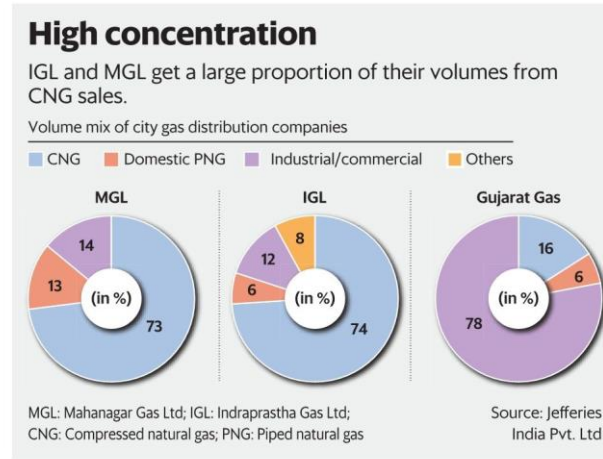
The oil and gas regulator, Petroleum and Natural Gas Regulatory Board's (PNGRB's) gazette notification for city gas distribution (CGD) removes a major overhang on competition for CGD companies. The share price of Indraprastha Gas Ltd (IGL) and Mahanagar Gas Ltd (MGL), which have significant exposure to metro regions of NCR and Mumbai, closed 9.5% and 13.7% higher, respectively, on Friday. Shares of Gujarat Gas, too, gained 4%.

CGD firms had marketing exclusivity in key geographical areas, which was about to end. There was also the fear that competition from oil and marketing companies would eat into market share, especially as CGDs share fuel outlets with oil marketing companies (OMCs) in metros.

PNGRB's notification, however, has given concessions, protecting the existing CGD business of firms.

"The notification restricts existing OMCs co-located in CNG outlets from selling CNG under open access route, mitigating any negative impact on the existing earnings of CGD

The share price of Indraprastha Gas and Mahanagar Gas closed 9.5% and 13.7% higher, respectively, on Friday



SATISH KUMAR/MINT

companies in the CNG segment. This is a major positive for CGD companies," said analysts at Jefferies India Pvt. Ltd. MGL and IGL benefit more because of higher CNG exposure. The broker pointed out that in the absence of the notification, about 20% of existing CNG volumes were at risk.

As such, investors are heaving a sigh of relief.

PNGRB has said in the notification that OMC outlets already selling

CNG will not be allowed to participate through the open access route. As such, there would be no competition from OMCs on existing outlets being shared. Also, new entrants will

have to set up their own outlets.

CGD firms are benefitting from rising demand for cleaner fuels, low natural gas prices, and increasing distribution network. However, the key for earnings growth remains revival of CNG volumes in metro towns facing risk from rising covid-19 cases.

Gujarat Gas seems well placed on the volume gains front. Its volume growth got a leg up from growing industrial demand in the Morbi cluster (Gujarat) that has already seen bans on certain other fuels. However, margins tend to be lower in this segment. MGL shares led the gains on Friday, also owing to relatively lower valuations. IGL is now trading at about 28 times FY22 earnings estimates, compared to MGL trading at 15.8 times.

Iraq says it won't seek exemption from Opec+ deal

Iraq will not ask Opec for exemption from a pact aimed at reducing output, and oil prices are expected to reach about \$50 at the beginning of 2021, the *al-Sabah* state newspaper cited the oil minister as saying in a report on Sunday. The minister said the commitment of members to the deal would help boost oil prices. **REUTERS**

नए नियमों से आईजीएल की लागत बढ़ेगी

शाइन जैकब

नई दिल्ली, 29 नवंबर

पाइपलाइन के लिए एकीकृत शुल्क ढांचा अपनाने के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) के निर्णय से इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (आईजीएल) की इनपुट लागत में करीब 5 से 6 फीसदी की वृद्धि होने के आसार हैं।

आईजीएल के प्रबंध निदेशक ए के जना ने कहा है कि एकीकृत शुल्क का असर मामूली होगा और इसका कुछ हिस्सा उपभोक्ताओं पर डाला जाएगा। हालांकि खुदरा कीमत में इजाफा मामूली होगा क्योंकि राष्ट्रीय पाइपलाइनों के लिए परिवहन शुल्क अंतिम रूप से उपभोक्ता मूल्य का केवल 12.5 फीसदी होता है।

जना ने बिजनेस स्टैंडर्ड से कहा, 'कुछ भौगोलिक क्षेत्रों में हमें कुछ असर नजर आएगा लेकिन वह बहुत ही मामूली होगा। निश्चित तौर पर



क्षेत्र के विनियामक का एकीकृत शुल्क ढांचा अपनाने का निर्णय

इनपुट लागत बढ़ने से कीमतों में वृद्धि होगी क्योंकि हमारा भौगोलिक क्षेत्र जोन 1 में नहीं है। इनपुट लागत में वृद्धि करीब 5-6 फीसदी की होगी।'

फिलहाल शुल्क पाइपलाइन से तय की जाने वाली दूरी के आधार पर

तय होता है। लंबी दूरी के लिए अधिक शुल्क भरना होता है। हालांकि, नए नियमन के मुताबिक दो जोन होंगे। 300 किलोमीटर से कम दूरी को जोन 1 में रखा जाएगा और उससे अधिक दूरी को दूसरे जोन में रखा जाएगा। दूसरे और तीसरे जोन के लिए शुल्क 100 फीसदी होगा और जोन 1 के लिए शुल्क उनके मुकाबले 40 फीसदी होगा। एकीकृत शुल्क ढांचा एकल गैस बाजार और ऊर्जा बास्केट में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी को मौजूदा 6 फीसदी से बढ़ाकर 15 फीसदी करने की सरकार की रणनीति का हिस्सा है। रिपोर्टों के आधार पर नए शुल्क ढांचे से स्रोत पर परिवहन लागत में 20 से 30 फीसदी का इजाफा होगा जबकि आंतरिक इलाकों में शुल्क में कमी आएगी। उद्योग से जुड़े एक व्यक्ति ने कहा, 'जिनका भी भौगोलिक क्षेत्र जोन 1 में आया उन्हें फायदा होगा और इससे बाहर जोन 2 और जोन 3 में आने

वालों को समस्या होगी।'

इस क्षेत्र में ओपन मार्केट पहुंच शुरू होने से मौजूदा कंपनियों के लिए कुछ सुरक्षा भी है। 26 नवंबर को पीएनजीआरबी ने शहरी गैस वितरण नेटवर्कों पर तीसरे पक्ष के मालवाहकों को पहुंच देने के लिए एक अंतिम नियमन जारी किया गया है।

कॉर्पोरेट रेटिंग इक्रा के उपाध्यक्ष और सह-प्रमुख अंकित पटेल ने कहा, 'नियमनों में तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) या उनके डीलरों/फ्रेंचाइज द्वारा परिचालित सीएनजी स्टेशनों पर और अधिक स्पष्टीकरण देने को छोड़कर पहुंच संहिता के अधिकांश पहलुओं में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पीएनजीआरबी ने फ्रेंचाइज/डीलरों (ओएमसी के सीएनजी/एलएनजी स्टेशनों सहित) के मौजूदा सीएनजी स्टेशनों को लेकर स्पष्ट किया है कि पहुंच की अनुमति देने के उद्देश्य के लिए मालवाहकों को तीसरा पक्ष नहीं समझा जाएगा।'



Oil prices seen remaining subdued into 2021

Business Standard
OPEC, ALLIES LIKELY TO EXTEND OUTPUT CUTS
Nov 30, 2020 | Delhi | Pg No.: 1,8 | | Sq Cm:374 | AVE: 925147 | PR Value: 4625737

WORLD P8
**OPEC, ALLIES LIKELY TO
EXTEND OUTPUT CUTS**



Opec, allies face seismic demand split; plan to extend output cuts

Bloc set to meet virtually to address key concerns on the back of a disastrous yr

JAVIER BLAS
29 November

As Opec+ ministers gather virtually this week, the city that traditionally hosts their meetings will be locked down. Vienna's Christmas markets will be closed, the famous Ringstrasse boulevard silent. For oil ministers, the scene should urge caution.

But while the Austrian capital provides a dramatic example of how the second wave of the pandemic is shutting down economies in Europe and the US, the global picture is more nuanced.

In Asia, the situation is almost the opposite to that of Vienna. The streets in India were full during the recent celebration of Diwali; China's Golden Week holiday saw millions take cars, trains and even planes to visit relatives across the country.

The east-west divide is an added conundrum for Opec+, which on November 30-December 1 needs to decide whether to delay a production increase slated for January — and if so, for how long. And there's another crucial divide in the global oil market: While gasoline and diesel demand have recovered to about 90 per cent of their normal level, consumption of jet fuel languishes at about 50 per cent.

"The size of the shock and the unevenness of its impacts imply a recovery process which



is far from smooth," said Bassam Fattouh, the head of the Oxford Institute for Energy Studies.

In private, Opec+ delegates talk about the imbalance in the recovery, both geographically and between refined products. Increasingly too, they talk about another segmentation: crude oil quality. The market for the denser more sulfurous crude, called heavy-sour, is tight, mostly because of production cuts from Saudi Arabia, Russia, and other big producers. But the market for so-called light-sweet is glutted, in part because Libyan barrels have come back to the market after a ceasefire, and European refiners are consuming less North Sea crude.

All those factors make the deliberations of Opec+ minis-

ters trickier. And they have just one blunt tool at their disposal: raising or cutting overall production. Opec+ nations do not target gasoline or jet-fuel production, but just crude.

There's also a geographical handicap: Most of their oil goes to Asia, where demand is strong, rather than Europe and America, where it's weaker. That means they can do little to address the glut where it matters. Even the quality is a problem: Opec pumps mostly heavy-sour crude, and can do relatively little to trim the excess of light-sweet crude.

There is some consolation. While the recovery in oil demand that started in May stuttered in October and November as the second wave took hold, it wasn't the same hit to the market as earlier this year. The lockdowns in Europe

aren't as severe as the first wave, and demand in Asia is surging — not just in China, but also in India, Japan and South Korea.

High frequency data for road usage shows a decline in early November of about 30 per cent from pre-Covid levels, compared to nearly 70 per cent in late March and early April, according to an index compiled by *Bloomberg News*. The most recent data suggests that road fuel demand bottomed out around November 15, and has been recovering since. With European nations easing lockdowns in the run-up to Christmas, demand is likely to recover further.

Pieced together, this all means the market isn't as bad as it looked just a few weeks ago. **BLOOMBERG**

तेल विपणन कंपनियों के लिए राहत

उज्ज्वल जौहरी
नई दिल्ली, 29 नवंबर

भले ही महामारी के वैश्विक प्रसार को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं, लेकिन कोविड-19 टीके को लेकर आ रही सकारात्मक खबरों से अगले साल वैश्विक आर्थिक सुधार आने और तेल एवं गैस मांग के लिए परिदृश्य में बदलाव आने की उम्मीद बढ़ गई है। इससे भारत पेट्रोलियम (बीपीसीएल), हिंदुस्तान पेट्रोलियम (ओएमसी) और इंडियन ऑयल (आईओसी) जैसी घरेलू तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) के लिए परिदृश्य में भी सुधार आया है। इन कंपनियों को मांग पर दबाव और कमजोर रिफाइनिंग मार्जिन से धारणा प्रभावित होने की चिंताओं का सामना करना पड़ा है।

अमेरिकी चुनावी घटनाक्रम पीछे छूटने से, ब्रोक्रेज फर्मों का ध्यान अब दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में आर्थिक सुधार पर केंद्रित होने की संभावना है। ओएमसी पहले से ही बीपीसीएल में निवेश की खबरों में हैं, जिसके सफल रहतने पर कंपनी के निवेशकों को अवसर हासिल करने का मौका मिल सकेगा।

इसके अलावा कंपनियों के लिए सितंबर तिमाही का प्रदर्शन उत्साहजनक है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि ओएमसी के शेयरों में सितंबर-अक्टूबर के निचले स्तरों से 19-31 प्रतिशत की तेजी आई है।

ओएमसी का दूसरी तिमाही का प्रदर्शन इन्वेंट्री बढ़त और मजबूत विपणन मार्जिन पर केंद्रित था, भले ही रिफाइनिंग मार्जिन कमजोर बना रहा। सभी तीनों ओएमसी का विपणन मार्जिन 5.9-6.6 रुपये प्रति लीटर के दायरे में दर्ज किया गया है जो अक्सर 2-3 रुपये के बीच रहता है। सकल रिफाइनिंग मार्जिन (जीआरएम, प्रति बैरल) 2.7 से 8.7 डॉलर के दायरे में रहा और इसे इन्वेंट्री में मजबूती की वजह से मदद मिली। इसलिए ओएमसी के



विपणन मार्जिन से आय को मदद मिलेगी, जबकि टीका पेश होने से रिफाइनिंग परिदृश्य में आ सकता है सुधार

लिए मुख्य जीआरएम सपाट से लेकर नकारात्मक रहा। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज (एमओएफएल) के विश्लेषकों का कहना है कि उदाहरण के लिए, आईओसी का रिफाइनिंग मार्जिन 8.6 डॉलर (9.6 डॉलर की इन्वेंट्री बढ़त शामिल) रहा। विश्लेषकों का कहना है कि मुख्य जीआरएम 1 डॉलर प्रति बैरल कमजोर रहा।

मॉर्गन स्टैनली के विश्लेषकों का कहना है कि भारतीय ओएमसी ने रिफाइनिंग संबंधित कमजोरी की भरपाई के लिए मजबूत विपणन आय दर्ज की है। उनका कहना है कि कंपनियां प्रभावी तरीके से ईंधन विपणन में सक्षम हैं। दूसरी तिमाही के बाद, ओएमसी ने आय में अपग्रेड भी दर्ज किए हैं। एमके ग्लोबल ने तीन ओएमसी के लिए वित्त वर्ष 2021 के आय अनुमानों में 9-44 प्रतिशत तक का इजाफा किया है।

विश्लेषकों का कहना है कि सितंबर तिमाही के प्रदर्शन से अन्य खास बात यह दिखी कि ओएमसी ने अपने विस्तार और पूंजीगत खर्च अनुमानों को बरकरार रखा है, जो उनके भविष्य के परिदृश्य का संकेत है।

The pandemic has left oil markets in Opec's hands

Opec's oil ministers have a few challenges to consider at a crucial summit next week, but for the first time in years the shale boom won't be at the top of the list. A devastating global pandemic and a reckoning with Wall Street appear to have broken the resolve of the shale wildcatters who turned the US into the world's biggest oil producer. Years of breakneck growth, at the expense of crude kingpins in West Asia and Russia, have come to an end. If there was ever any doubt, it's now abundantly clear who has the upper hand in the global oil market. "In the future, certainly we believe Opec will be the swing producer — really, totally in control of oil prices," Bill Thomas, CEO of EOG Resources Inc., said earlier this month.

BLOOMBERG

CAUGHT | IN COVID

Output from shale wells typically declines in a matter of months, so new ones need to be drilled

Pandemic has broken shale and left oil markets in Opec hands

KEVIN CROWLEY,
DAVID WETHE &
SHEELA TOBSEN
NOV. 29

Opec's oil ministers have a few challenges to consider at a crucial summit on Monday, but for the first time in years the shale boom won't be at the top of the list.

A devastating global pandemic and a reckoning with Wall Street appear to have broken the resolve of the shale wildcatters who turned the US into the world's biggest oil producer. Years of breakneck growth, at the expense of crude kingpins in the Middle East and Russia, have come to an end. If there was ever any doubt, it's now abundantly clear who has the upper hand in the global oil market.

"In the future, certainly we believe Opec will be the swing producer - really,

totally in control of oil prices," Bill Thomas, chief executive officer of EOG Resources Inc, the biggest independent shale producer by market value, said earlier this month. "We don't want to put Opec in a situation where they feel threatened, like we're taking market share while they're propping up oil prices."

The shale industry's prudence, also echoed by the CEOs of Pioneer Natural Resources Co and Occidental Petroleum Corp, means that production will probably flatten after a steep plunge this year: US oil output will end 2021 close to 11 million barrels a day, about the same as it is now, according to forecasters IHS Markit, Rystad Energy, Enverus and the US Energy Information Administration.

"I see no more growth until 2022, 2023, and it will



be very, very light in regard to the US shale industry ever growing again," Pioneer CEO Scott Sheffield, who'll run the fourth-largest shale operation in the country after his company completes the takeover of Parsley Energy Inc, said in an interview.

That will surely come as a relief to Opec and its allies.

At the start of 2020, the group's efforts to control prices were facing increasing difficulties. The breakthroughs in horizontal drilling and

fracking that ushered in the shale revolution made it look as though US production growth might never end. Output surpassed 13 million barrels a day for the first time in February.

Then Covid-19 hit, people around the world stopped driving and flying, and the oil market crashed. President Donald Trump brokered a historic deal with Opec in April to remove almost a 10th of global production from the market. He said the US contribution would come in the form of market-driv-

en cuts.

That pledge was delivered faster than most predicted, and it made a huge difference. Investors who were already tiring of the shale industry's cash-burning spree retreated from the sector, and several producers went bankrupt. Before the summer was over, US output had collapsed by 3.4 million barrels a day, almost the same as removing the United Arab Emirates at peak production. Output from shale wells typically declines in a matter of months, so new ones need to be drilled and fracked just to maintain production at current levels. A recent uptick in drilling and fracking doesn't seem to be enough to ensure production growth.

Since hitting bottom in the summer, the number of rigs searching for crude in shale fields has increased

by 69 to 241 last week, according to data from Baker Hughes Co. That's still down from 683 in March. Similarly, the number of fracking crews in the once vibrant Permian Basin straddling Texas and New Mexico has increased to 63, an improvement from a meagre 20 in June, data from Primary Vision Inc show. But that's less than half the 146 teams that were pumping mixtures of water, chemicals and sand into wells in January to release oil from shale rock in the area.

It's as though the US suddenly went from being a thorn in Opec's side to being an unofficial member of the cartel's alliance with Russia and other producing nations. Since June, benchmark US oil prices have been remarkably stable, hovering around \$40 a barrel, and

that's how Opec likes it.

While shale's retreat has made Opec's life easier, for the US oil industry it's been brutal. There have been 43 bankruptcies of exploration and production companies this year through October, according to a report from law firm Haynes & Boone.

Shale may be down but it's certainly not out, though. The US is still an oil superpower, and will remain so for years to come. And there's always the possibility that higher prices will get explorers drilling and fracking relentlessly like before. A sustained price rise to \$50 a barrel will "trigger growth again," according to Bernadette Johnson, vice president for strategy and analytics at Enverus. At \$60 a barrel, US shale will come back strongly, she said.

—Bloomberg

रानीखेड़ा क्षेत्र में लगाया जाएगा एक और संयंत्र

जनसत्ता संवाददाता

नई दिल्ली, 29 नवंबर।

उत्तरी दिल्ली के महापौर ने रविवार को भलस्वा कचरा पट्टी का निरीक्षण करते हुए कहा कि अब रानीखेड़ा क्षेत्र में एक और वेस्ट टू एनर्जी संयंत्र लगाया जाएगा। इससे लोगों को कचरा से मुक्ति मिलेगी। उत्तरी दिल्ली के महापौर जय प्रकाश ने रविवार को भलस्वा का निरीक्षण करते हुए बताया कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ मिलकर उत्तरी दिल्ली नगर निगम 1000 करोड़ रुपए की लागत से रानीखेड़ा में एक और अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र की स्थापना करने जा रही है। उन्होंने बताया कि इससे उत्तरी दिल्ली नगर निगम के क्षेत्र में एकत्रित किए गए कचरे के पूर्ण निपटान में मदद मिलेगी।

महापौर ने बताया कि हमने 15 मशीन स्थापित की हैं जो कि भलस्वा में कूड़े के निपटान में लगी हुई हैं। अब तक यहां कूड़े की ऊंचाई को लगभग 30 फीट तक कम करने में सक्षम रहे हैं। उन्होंने दिल्ली सरकार से निगमों को बकाया 13000 करोड़ रुपए फंड जारी करने की मांग की ताकि कल्याणकारी परियोजनाएं शुरू की जा सकें।